गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 259
दि. 20.01.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

एसी/एसटी एक्ट पर 'सुप्रीम' फैसला: सिर्फ गाली देना अपराध नहीं, जातिगत अपमान का इरादा साबित करना जरूरी

(जीएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल अपशब्द बोल देना या सामान्य गाली-गलौज करना इस कानून के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। किसी व्यक्ति पर एसी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा तभी चलाया जा सकता है, जब यह ठोस रूप से साबित हो कि अपमान या धमकी विशेष रूप से उसकी जाति को निशाना बनाकर दी गई हो और उसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से जातिगत बेइज्जती करना रहा हो।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि इस विशेष कानून की धाराओं का प्रयोग बहुत सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। अदालत ने माना कि कई मामलों में बिना पर्याप्त साक्ष्यों के इस कठोर कानून का सहारा ले लिया जाता है, जिससे निर्दोष लोग लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते हैं। न्यायालय ने दो टूक कहा कि एसी/एसटी एक्ट सामाजिक न्याय और सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया है, न कि व्यक्तिगत झगड़ों को निपटाने का औजार बनने के लिए।

यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने केशव महतो उर्फ केशव कुमार महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। महतो ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक आंगनवाड़ी केंद्र में गाली-गलौज की और

मारपीट की। इसी घटना के आधार पर उनके खिलाफ एसी/एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोपों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं था कि अपमान जाति के आधार पर किया गया था। इसी आधार पर शीर्ष अदालत ने आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह रद्द कर दिया।

पीठ ने अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि दोनों निचली अदालतों ने यह देखे बिना ही कार्यवाही आगे बढ़ा दी कि शिकायत में जातिगत अपमान का कोई ठोस उल्लेख है भी या नहीं। न प्राथमिकी में और न ही पुलिस की चार्जशीट में यह बताया गया कि आरोपी ने पीड़ित की जाति को लेकर कोई टिप्पणी की या उसे जाति के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश की। ऐसे में इस कानून के तहत मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की धारा 3(1)(r) की विस्तार से व्याख्या करते हुए बताया कि इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए दो अनिवार्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त यह है कि शिकायतकर्ता वास्तव में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य हो। दूसरी और सबसे अहम शर्त यह है कि आरोपी द्वारा किया गया अपमान या धमकी विशेष रूप से इस कारण दी गई हो कि सामने वाला व्यक्ति उस समुदाय से संबंध रखता है। यदि यह तत्व अनुपस्थित है, तो मामला इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल यह तथ्य काफी नहीं है कि आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी थी। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अपमान करने के पीछे वास्तविक मंशा जातिगत घृणा या भेदभाव थी। आपराधिक कानून में 'मेन्स रिया' यानी अपराध करने का इरादा सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है और इसके बिना सजा नहीं दी जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसी/एसटी एक्ट तभी लागू होगा जब अपमान सार्वजनिक स्थान पर किया गया हो और उसका सीधा उद्देश्य पीड़ित की सामाजिक गरिमा को ठेस पहुंचाना हो। यदि दो व्यक्तियों के बीच सामान्य विवाद, झगड़ा या मारपीट हुई है और उसमें जातिगत टिप्पणी शामिल नहीं है, तो ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता की सामान्य धाराओं के तहत देखा जाना चाहिए, न कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत।

यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस कानून के दुरुपयोग की शिकायतें बढ़ी हैं। अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि कानून का मूल उद्देश्य दलित और आदिवासी समुदायों को ऐतिहासिक उत्पीड़न से बचाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन देना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर आपसी विवाद को इसी कानून के दायरे में ला दिया जाए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में ट्रायल कोर्ट्स के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। अब समन जारी करने से पहले अदालतों को यह देखना होगा कि क्या वास्तव में जातिगत अपमान का इरादा मौजूद है या नहीं। इससे एक ओर निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर वास्तविक पीड़ितों के मामलों को अधिक मजबूती भी मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। एसी/एसटी एक्ट एक संवेदनशील और सख्त कानून है, इसलिए इसका प्रयोग तथ्यों और साक्ष्यों की गहन जांच के बाद ही होना चाहिए। यह फैसला न केवल कानूनी प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाएगा, बल्कि समाज में कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत करेगा।

भारत आए यूएई के राष्ट्रपति, प्रोटोकॉल तोड़ एयरपोर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी

(जीएनएस)। नई दिल्लीः संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार शाम जब दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो स्वागत का दृश्य सामान्य राजनयिक औपचारिकताओं से कहीं अधिक आत्मीय और गर्मजोशी भरा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं प्रोटोकॉल की परंपरा से हटकर एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने गले मिलकर अतिथि का स्वागत किया। यह केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि दो देशों के बीच गहरे होते भरोसे, रणनीतिक साझेदारी और व्यक्तिगत मित्रता का प्रतीक क्षण था। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूएई के संबंध जिस गति से आगे बढ़े हैं, यह यात्रा उसी यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। शेख नाहयान का यह दौरा राष्ट्रपति बनने के बाद उनका तीसरा आधिकारिक भारत आगमन है, जबकि बीते एक दशक में वे पांचवीं बार भारत की धरती पर कदम रख रहे हैं। किसी भी खाड़ी देश के सर्वोच्च नेता का इतने कम अंतराल में बार-बार भारत आना इस बात का संकेत है कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत यूएई की विदेश नीति के केंद्र में आ चुका है। इससे पहले अबू धाबी के शहजादा और दुबई के क्राउन प्रिंस की यात्राओं ने दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊर्जा दी थी, लेकिन राष्ट्रपति का यह दौरा उन तमाम पहलों को राजनीतिक दिशा और

रणनीतिक गहराई देने वाला माना जा रहा है। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया गहरे भू-राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। गाजा संकट, ईरान-अमेरिका तनाव, लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमलों और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। ऐसे माहौल में यूएई भारत को एक संतुलित, भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देख रहा है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, सभी पक्षों से संवाद बनाए रखने की क्षमता और वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व ने अबू धाबी के नीति निर्धारकों को नई संभावनाओं की ओर आकर्षित किया है।

खाड़ी राजनीति में हाल के दिनों में सऊदी अरब और यूएई के बीच उभरे मतभेद भी इस यात्रा की पृष्ठभूमि में मौजूद हैं। दक्षिणी यमन को लेकर दोनों देशों के अलग-अलग हित टकरा रहे हैं। सऊदी अरब जहां यमन की एकता और अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है, वहीं यूएई पर वहां के कुछ स्थानीय समूहों को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। लाल सागर और बाब-अल-मंडेब जैसे सामरिक जलमार्गों पर नियंत्रण की होड़ ने इस प्रतिस्पर्धा को और जटिल बना दिया है। ऐसी परिस्थिति में भारत के साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी यूएई के लिए संतुलन साधने का एक अहम माध्यम बन सकती है।

लाल सागर का क्षेत्र आज वैश्विक व्यापार की धमनियों में गिना जाता है। एशिया से यूरोप जाने वाला बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। हाल के महीनों में वहां बढ़ी असुरक्षा ने ऊर्जा आपूर्ति और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है। भारत, जो अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी से आयात करता है, इस क्षेत्र में स्थिरता का स्वाभाविक पक्षधर है। इसलिए दोनों नेताओं के बीच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, खुफिया सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की पूरी संभावना है।

द्विपक्षीय संबंधों की रीढ़ आर्थिक सहयोग रहा है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों का व्यापार रिकॉर्ड गति से बढ़ा है। यूएई आज भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शामिल है और खाड़ी में भारतीय निवेश का सबसे बड़ा केंद्र भी है। इस यात्रा के दौरान ऊर्जा, फिनटेक, डिजिटल भुगतान, खाद्य सुरक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भविष्य के क्षेत्रों में नए समझौतों की उम्मीद की जा रही है। यूएई भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार और कुशल मानव संसाधन को अपनी आर्थिक विविधीकरण योजना के लिए महत्वपूर्ण मानता है।

रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी संबंध नई दिशा ले रहे हैं। हिंद महासागर से लेकर पश्चिम एशिया तक फैली चुनौतियों के बीच दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल यूएई के लिए निवेश का आकर्षक मंच बन सकती है, वहीं भारत को खाड़ी क्षेत्र में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार मिल रहा है। यह सहयोग केवल हथियारों की खरीद-बिक्री तक सीमित न होकर सामरिक सोच की साझेदारी में बदलता दिख रहा है।

भारत में रहने वाला लगभग 35 लाख का भारतीय समुदाय इन रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी है। यूएई की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में भारतीय श्रमिकों, पेशेवरों और कारोबारियों का बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रपति नाहयान अक्सर इस समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताते रहे हैं।

चट्टोग्राम वकील हत्याकांड: चिन्मय कृष्ण दास समेत 39 आरोपियों पर हत्या और साजिश के आरोप तय

(जीएनएस)। ढाका और चट्टोग्राम की अदालतों के इतिहास में यह मुकदमा सबसे संवेदनशील मामलों में से एक माना जा रहा है। बांग्लादेश की विशेष स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल ने चट्टोग्राम के चर्चित वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या के मामले में 'संम्मिलितो सनातनी जागरण जोत' के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास सहित कुल 39 लोगों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। न्यायाधीश मोहम्मद जाहिदुल हक की अदालत में लंबी सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए हत्या की धारा 302 और आपराधिक साजिश की धारा 109 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया। इस फैसले के साथ ही यह मामला अब पूरी तरह से ट्रायल के चरण में प्रवेश कर गया है।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत परिसर का माहौल असाधारण रूप से तनावपूर्ण रहा। सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही आशंका थी कि यह मामला धार्मिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील रूप ले सकता है, इसलिए

लगभग 900 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई। पूरे कोर्ट परिसर को बैरिकेड्स से घेर दिया गया था और आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन जांच की जा रही थी। चिन्मय कृष्ण दास को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। उन्होंने न्यायाधीश के सामने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं तथा वे निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के माध्यम से सच्चाई सामने लाने की मांग करते हैं।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह हत्याकांड अचानक हुई घटना नहीं था, बल्कि इसके पीछे संगठित भीड़ और सुनियोजित साजिश काम कर रही थी। पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि 26 नवंबर 2024 को जमानत याचिका खारिज होने के बाद अदालत परिसर के बाहर भड़की हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने जानबूझकर वकील सैफुल इस्लाम अलिफ को निशाना बनाया। उन पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। अभियोजन का तर्क है कि भीड़ को उकसाने और हिंसा को दिशा देने में कुछ प्रमुख लोगों की भूमिका रही, जिनमें चिन्मय कृष्ण दास का नाम प्रमुखता से लिया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि भी उतनी ही जटिल है। चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को ढाका से एक पुराने देशद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंदू समुदाय के एक हिस्से में तीखी प्रतिक्रिया हुई और विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। 26 नवंबर को जब चट्टोग्राम की अदालत ने उनकी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी, तब अदालत परिसर के बाहर हजारों समर्थक जमा हो गए। भीड़ और पुलिस के बीच झड़प ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। इसी अफरातफरी में वकील अलिफ की हत्या हुई, जिसने पूरे बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद कई जिलों में तनाव फैल गया और सरकार को शांति बहाल करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।

अभियोजन ने अदालत को बताया कि अब तक की जांच में डिजिटल साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट होता है कि हिंसा स्वतःस्फूर्त नहीं थी। कुछ लोगों ने भीड़ को भड़काने के लिए भाषण दिए और पुलिस पर हमले के लिए उकसाया। चार्जशीट में 39 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनमें से 23 इस समय न्यायिक हिरासत में हैं जबकि 16 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।

जम्मू–कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंक से जंग मुठभेड़ में घायल हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद

(जीएनएस)। किश्तवाड़। जम्मू–कश्मीर के पहाड़ी जिले किश्तवाड़ में आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान के दौरान देश ने एक और वीर सपूत खो दिया। रविवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में घायल हुए हवलदार गजेंद्र सिंह ने सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनकी शहादत ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि कश्मीर की वादियों में अमन की कीमत हमारे जवान अपने खून से चुका रहे हैं। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं सुरक्षा बलों का मनोबल पहले से ज्यादा मजबूत होकर आतंकियों के सफाए के लिए डटा हुआ है।

घटना किश्तवाड़ के तरू बेल्ट के मंडराल–सिंहपोरा इलाके के पास स्थित सोनार गांव के घने जंगलों में हुई। खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर सेना ने रविवार को 'ऑपरेशन त्राशी–1' शुरू किया था। जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद से जुड़े दो से तीन आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं। जैसे ही सुरक्षाबलों की टुकड़ी संदिग्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, आतंकियों ने घात लगाकर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसमें आठ जवान घायल हो गए थे।

घायलों को तुरंत हेलीकॉप्टर और एंबुलेंस की मदद से नजदीकी सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन हवलदार गजेंद्र सिंह की हालत गंभीर बनी रही और सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। गजेंद्र सिंह भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स इकाई में तैनात थे और कई आतंक रोधी अभियानों का अनुभव रखते थे। उनके साथी बताते हैं कि वे बेहद साहसी, अनुशासित और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित जवान थे। उनकी शहादत से पूरी बटालियन गमगीन है, लेकिन साथ ही आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प भी और मजबूत हो गया है।

मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। सेना, जम्मू–कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीमें जंगलों की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। आधुनिक ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरों और स्निफर डॉग्स की मदद से आतंकियों की हर संभावित लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि आतंकी ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों का फायदा उठाकर बार–बार स्थान बदल रहे हैं, लेकिन उनके बच निकलने की संभावना बेहद कम है।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हाल के महीनों में किश्तवाड़ और डोडा बेल्ट में आतंकियों की गतिविधियां फिर से बढ़ने लगी हैं। सीमा पार से घुसपैठ कर आए कुछ आतंकी छोटे–छोटे समूहों में बंटकर स्थानीय युवाओं को भड़काने और सुरक्षाबलों पर हमले की फिराक में हैं। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि ये आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं और उन्हें पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से लगातार निर्देश मिल रहे हैं। इसी कारण सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया है।

स्थानीय लोगों में भी इस घटना के बाद डर और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि वर्षों बाद इलाके में फिर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि अधिकांश ग्रामीण सुरक्षाबलों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सेना की वजह से ही वे सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं। कई युवाओं ने स्वेच्छा से तलाशी अभियान में मदद की पेशकश भी की है।

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी आतंकी या तो मारे नहीं जाते या गिरफ्तार नहीं हो जाते। किसी भी निर्दोष नागरिक को नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इलाके के स्कूलों और संवेदनशील रास्तों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। साथ ही आसपास के जिलों में भी नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है, ताकि आतंकी भाग न सकें।

कांग्रेस का बड़ा आरोपः भाजपा के इशारे पर मतदाता सूची से काटे जा रहे लाखों नाम

(जीएनएस)। जयपुर। राजस्थान की राजनीति में एक नया और गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की आड़ में कांग्रेस समर्थक लाखों मतदाताओं के नाम योजनाबद्ध तरीके से काटे जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि यह लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला है और यदि समय रहते इस साजिश को नहीं रोका गया तो आने वाले चुनावों की निष्पक्षता पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। उन्होंने मांग की कि नाम हटाने के लिए जमा किए गए सभी फॉर्मों की फॉरेंसिक जांच कराई जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हाल ही में जारी मसौदा मतदाता सूची में लगभग 45 लाख लोगों को अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत की श्रेणी में दिखाया गया है, जो असामान्य रूप से बड़ा आंकड़ा है। डोटासरा ने सवाल उठाया कि क्या कुछ ही महीनों में इतने बड़े पैमाने पर लोग अचानक राज्य छोड़कर चले गए या उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन इलाकों में कांग्रेस को परंपरागत रूप से अधिक समर्थन मिलता है, वहीं सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। यह संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा चुनाव मैदान में जनता का सामना करने से डर रही है, इसलिए वह प्रशासनिक रास्तों से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव डालकर हजारों आपत्तियां दाखिल करवाई गईं। कई मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम से सैकड़ों फॉर्म जमा किए गए, जिनमें हस्ताक्षर तक मेल नहीं खाते। पार्टी का आरोप है कि भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं को सरकारी तंत्र का संरक्षण देकर यह काम कराया गया। डोटासरा ने कहा कि हमारे पास ऐसे अनेक प्रमाण हैं जहां जीवित और नियमित मतदान करने वाले लोगों के नाम भी सूची से हटा दिए गए हैं। कई बुजुर्गों और महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह न केवल अवैधानिक है बल्कि अमानवीय भी है।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में है। आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था माना जाता है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से प्रक्रिया चलाई गई, उससे यह भरोसा टूट रहा है। जूली ने कहा कि बार-बार शिकायत देने के बावजूद आयोग ने ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही, जब तक जांच पूरी न हो जाए, तब तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित न की जाए।

इस मुद्दे पर कांग्रेस सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। पार्टी ने जिला और ब्लॉक स्तर पर 'मतदाता बचाओ अभियान' शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों के नामों की जांच करेंगे और आपत्तियां दर्ज कराएंगे। डोटासरा ने कहा कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत है और उसी ताकत को छीनने की कोशिश की जा रही है। हम किसी भी कीमत पर यह अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची की जांच करें और गड़बड़ी पाए जाने पर खुलकर सामने आएं। कांग्रेस के आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

बेरोजगारी का दंश

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट ने देश में रोजगार की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर माह में बेरोजगारी दर बढ़कर 4.8 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो यह संकेत देती है कि आर्थिक विकास की मौजूदा रफ्तार आम लोगों के लिए पर्याप्त अवसर नहीं बना पा रही है। भारत को विश्व में युवाओं के देश के रूप में जाना जाता है, परंतु यह युवा शक्ति यदि बेरोजगारी के बोझ तले दबती रही तो जनसांख्यिकीय लाभांश धीरे धीरे जनसांख्यिकीय चुनौती में बदल सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देकर राष्ट्र निर्माण के काम में लगाया जाए।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर ग्रामीण इलाकों से अधिक दर्ज की गई है। शहरों में पंद्रह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी 6.7 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि गांवों में यह 3.9 प्रतिशत के आसपास स्थिर है। आम धारणा यह रही है कि शहर रोजगार के केंद्र होते हैं, परंतु आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। महानगरों में बढ़ती जनसंख्या, सीमित औद्योगिक विस्तार और सेवा क्षेत्र में धीमी मांग के कारण युवाओं को मनचाहा काम नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति सामाजिक असंतोष को भी जन्म दे रही है।

किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास दर तभी अर्थपूर्ण मानी जाती है जब उसके साथ रोजगार के नये अवसर भी पैदा हों। केवल सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ते आंकड़े आम नागरिक के जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। यदि कारखानों, दफ्तरों और छोटे उद्योगों में नौकरियां नहीं बढ़ेंगी तो विकास का लाभ कुछ सीमित हाथों तक सिमट जाएगा। नीति बनाने वालों को यह गंभीरता से सोचना होगा कि दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत में रोजगार सृजन अपेक्षित स्तर पर क्यों नहीं हो पा रहा है।

सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सिकुड़ना चिंता का विषय है। एक ओर संगठित क्षेत्र में नई भर्तियां सीमित हो रही हैं, दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र भी दबाव में है। लघु और मध्यम उद्योग, जो रोजगार के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं, अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पूंजी की कमी, महंगी बिजली, जटिल नियम और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण ये उद्योग अपेक्षित विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। परिणामस्वरूप लाखों युवाओं के लिए रोजगार का द्वार संकरा होता जा रहा है।

तकनीकी बदलाव भी रोजगार के स्वरूप को तेजी से बदल रहे हैं। कृत्रिम मेधा और डिजिटलीकरण ने उत्पादन की प्रक्रिया को अधिक स्वचालित बना दिया है। कई क्षेत्रों में मशीनें वह काम कर रही हैं जो पहले मनुष्य करते थे। इससे पारंपरिक नौकरियों में कमी आई है। प्रश्न यह है कि क्या हमारा समाज इस बदलाव के लिए तैयार है। यदि युवाओं को नई तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं किया गया तो बेरोजगारी की समस्या और गहरी हो सकती है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और कौशल विकास जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए, परंतु जमीनी स्तर पर इनके परिणाम उतने उत्साहजनक नहीं दिख रहे। प्रशिक्षण केंद्रों से प्रमाणपत्र तो मिल रहे हैं, परंतु उन प्रमाणपत्रों के आधार पर स्थायी रोजगार नहीं मिल पा रहा। कई बार पाठ्यक्रम उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से मेल नहीं खाते। शिक्षा व्यवस्था भी तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम नहीं मिला पा रही है। जब तक शिक्षा और कौशल के बीच तालमेल नहीं होगा, तब तक रोजगार सृजन की कोशिशें अधूरी रहेंगी।

सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं में गहरी निराशा है। बढ़ती आबादी के बावजूद सरकारी पद लगातार घट रहे हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, पारदर्शिता की कमी और परीक्षा प्रणाली की जटिलताओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में समय और संसाधन खर्च करते हैं, परंतु सीमित पदों के कारण अधिकांश को निराश होना पड़ता है। यह स्थिति मानसिक दबाव और सामाजिक अस्थिरता को भी जन्म देती है। बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक चुनौती भी है। जब युवाओं को काम नहीं मिलता तो उनकी क्रय शक्ति घटती है, परिवारों की आय प्रभावित होती है और बाजार की मांग कमजोर पड़ती है। इससे आर्थिक चक्र धीमा हो जाता है। रोजगार बढ़ने से उपभोक्ता मांग में वृद्धि होती है, महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिलती है और समाज में आत्मविश्वास पैदा होता है। इसलिए रोजगार सृजन को विकास नीति के केंद्र में रखना अनिवार्य है। देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में संतुलित विस्तार जरूरी है। छोटे उद्यमों को सस्ती पूंजी, सरल नियम और तकनीकी सहयोग दिया जाए। स्टार्टअप संस्कृति को गांवों और छोटे शहरों तक ले जाना होगा। स्थानीय जरूरतों के अनुरूप रोजगार मॉडल तैयार करने होंगे ताकि पलायन की मजबूरी कम हो सके।

मोदी सरकार की सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा के निहितार्थ

“दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय, ‘युगे-युगीन भारत’ की पहली गैलरी साल के आखिर तक खुल जाएगी। इसी कड़ी में दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय व अयोध्या में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय का निर्माण भी हो रहा है, जो सांस्कृतिक तौर पर महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। जरूरी है कि सरकारें देश में ऐसी सभी गौरवपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों पर एक समान ध्यान दें।

भारत भले ही अपने सबसे महत्वपूर्ण विदेशी भागीदार, अमेरिका के साथ राजनीतिक द्वंद्व में उलझा हो, जबकि अर्थव्यवस्था, जैसा कि जाने-माने वित्तीय पत्रकार टीएन नाइनन ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में इन कॉलम में बताया था -‘मिलनसार होने की बजाय शर्मीली ज्यादा’ है - लेकिन सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भव्य पैमाने पर पेश करने की सरकार की ‘कभी हार न मानने वाली’ महत्वाकांक्षा जस-की-तस है। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय, ‘युगे-युगीन भारत’ की पहली गैलरी साल के आखिर तक खुल जाएगी।

इसका पैमाना निश्चित रूप से बहुत विशाल है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक के भारत की गाथा बताने वाली 1,00,000 कलाकृतियों को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की 30 दीर्घाओं में प्रदर्शित जाएगा, लुटियंस दिल्ली में ब्रिटिश राज की ये इमारतें नौकरशाही के आला अधिकारियों का पिछले सौ सालों से कार्यस्थल रहा है। संग्रहालय में बारे में कुछ ऐसा है जो मोदी सरकार को खासतौर पर भाता है। शायद, बहुजन समाज पार्टी की दलित नेता मायावती की तरह — जिनके खुद के और उनके गुरु कांशी राम और बाबा साहेब अंबेडकर के स्मारक लखनऊ और दिल्ली के बाहरी इलाकों में जगह-जगह बने हैं-मोदी को ज्ञात होगा कि आप उनसे नफरत करें या प्यार, लेकिन स्मारकों को समय की परीक्षा झेलनी पड़ती है। (यही वजह है कि 1991 के आखिर में जब यह स्पष्ट हो गया कि सोवियत संघ बिखरेगा, तो प्रति-क्रांतिकारियों ने सबसे पहले लेनिन और मार्क्स की मूर्तियों पर ही हमला बोला था।) और इसीलिए, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 11 सालों में नई दिल्ली का स्वरूप धीरे-धीरे फिर से बदलकर नया रूप दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री संग्रहालय, जहां मोदी समेत हर विगत प्रधानमंत्री के लिए एक गैलरी होगी- जिसका ज़िक्र दिल्ली आने वाली शताब्दी ट्रेनों के पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर होता है -से लेकर युगे-युगीन भारत तक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा का भारत के हृदय में एक खास यादगार बनाने की महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन बेमिसाल है। प्रभावशाली तथ्य यह कि भाजपा के लिए कुछ भी छोटा नहीं। दिसंबर के आखिरी हफ़्ते में जालंधर में हुए हरिवल्लभ संगीत समारोह में, जिसने अपनी 150वीं सालगिरह मनाई है, संस्कृति मंत्री गजेंद्र शेखावत नहीं आ पाए – इसलिए उन्होंने एक वीडियो संदेश भेजा जिसमें कहा कि सरकार को देश के सबसे पुराने संगीत समारोह के लिए एक ऑडिटोरियम बनाने में खुशी होगी। तालियों के बीच जो अनकहा संदेश संलग्न था, वह यह कि बीजेपी पंजाब की लुप्त हो रही विरासत को पुनर्स्थापित करने में मदद हेतु कुछ भी करेगी– और अगर पंजाब के लोग उसे वोट देकर यह एहसान चुकाते हैं, तो इससे ज़रूर मदद मिलेगी।इसीलिए दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में उद्‌घाटन की गई पिपरहवा बुद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी में रखी वस्तुओं के विवरण पर बहुत कम ध्यान दिया देखकर हैरानी हुई। जो लोग इसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि औपनिवेशिक ब्रिटिश हुकूमत के एक इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने 1898 में बर्डपुर एस्टेट के तहत आते पिपरहवा नामक गांव में कुछ रत्न, गौतम बुद्ध के अस्थि अवशेष और राख वाले पांच छोटे कलश खोज निकाले थे, नेपाल सीमा के दक्षिण में कई एस्टेट्स का प्रबंधन उनके जिम्मे था। साल 2025 में, जब पेप्पे के वंशजों ने हांगकॉन्ग में अपने पास रखे बुद्ध अवशेषों की नीलामी करने का फैसला किया, उससे देशभर में खलबली मची, तत्पश्चात केंद्र सरकार ने गोदरेज इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर रत्नों व अवशेषों को खरीदने और वापस मातृभूमि लाने का फैसला किया।

प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था : ‘यह हर भारतीय को गौरवान्वित महसूस कराएगा कि भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष 127 साल लंबे अरसे बाद घर (भारत) वापस आ गए हैं’। निश्चित ही, भारत को एक प्राचीन सभ्यता, सिंधु घाटी, और एक प्राचीन विचारधारा,बौद्ध धर्म के सही उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा देखना प्रभावशाली है।

वहां पर वही थे, आपके सामने एक बुलेटप्रूफ केस में, शानदार रत्न। उन्हें निहारते हुए आप ‘चांदी और सोने में उकेरे तारे, तश्तरियों में सोने की पत्तियों में उभरे बौद्ध प्रतीक और नाना आकार के मोती, मनके, लाल या सफेद कार्नेलियन, एमेथिस्ट, पुखराज, गार्नेट, मूंगा और क्रिस्टल पर तराशकर बनाए तारे और फूल’–यह सारी जानकारी ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पिपराहवा डॉट कॉम’ से लेनी पड़ी क्योंकि प्रदर्शनी में यह सब जानकारी उपलब्ध नहीं, न तो वहां मौजूद युवा किंतु खुद अनभिज्ञ स्वयंसेवक बता पाए और न ही प्रदर्शनी की आयोजक डिज़ाइन फैक्ट्री इंडिया (डीएफआई) नामक कंपनी दे पाई। गौरतलब है कि उक्त कपंनी अपनी मशहूरी इस दावे के आधार पर करती है कि उसने वड़नगर में नगर का ‘बुद्ध से नाता’ थीम पर एक संग्रहालय बनाया है, और भुज में 2001 के भूकंप की याद में एक संग्रहालय भी बनाया है। प्रदर्शनी में बुद्ध को जीवंत करती शानदार मूर्तियां भी रखी गईं, जिन्हें कोलकाता के भारतीय संग्रहालय, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय म्यूज़ियम और देश के अन्य कई संग्रहालयों से लाया गया है। इनमें से कई मूर्तियां कभी खैबर-पख्तूनख्वा के उन हिस्सों से आई थीं, जो अब पाकिस्तान में हैं, सिवाय इसके कि सूचना पट्टी पर ‘पाकिस्तान’ शब्द को ‘अविभाजित भारत’ से बदल दिया गया है। कुछ पेंटिंग्स ‘रिक्रिएटिड’ - जिसका मतलब है वे जिस संग्रहालय में रखी थीं, वहां उनकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि उन्हें दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं।

अब हज़ार साल पुरानी मूर्तियों को गौर से देखने पर आपको भान होता है कि उन्हें साफ किया गया है –दशकों की जमी धूल,गंदगी हटाने के बाद वे इतनी चमक रही थी। डीएफआई आपकी इस परिकल्पना की पुष्टि करती है। उम्मीद करें कि सफाई करने वालों ने यह करने में उच्च गुणवत्ता वाले द्रवों का इस्तेमाल किया होगा जो आगे चलकर पत्थर का क्षरण न करे- यह प्रक्रिया क्या थी, जानकर अच्छा लगेगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज और सरकार के बीच इस प्रकार का पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भविष्य के लिए एक मॉडल है। हालांकि, साफ नहीं कि क्या गोदरेज वालों ने रत्न अवशेष देश को दान कर दिए हैं या सरकार ने उन्हें खरीद लिया है।

ऐसे में जब दिल्ली के बीचोंबीच युगे-युगीन भारत संग्रहालय आकार ले रहा है, जोकि प्रधानमंत्री के नए आवास से कुछ ही दूरी पर है और जिसका निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है, अपनी दृष्टि अयोध्या पर डालें, जहां राम मंदिर से सटा भारतीय मंदिर वास्तुकला पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह निजी भागीदारी वाली परियोजना है, लेकिन सरकार इस पर निगाह रखे है। इसकी शानदार परिकल्पना वास्तुकला कंपनी ज़ाहा हदीद आर्किटेक्चरल कंसर्न की है –हालांकि युगे-युगीन भारत संग्रहालय बनाने का ठेका इस कंपनी ने देबाशीष गुहा के आर्कोप कॉन्सोर्टियम व लॉस एंजिल्स स्थित कुलपत यंत्रसास्त के हाथों गंवाया है–जबकि परियोजना को फंडिंग टाटा की सहायक कंपनी इकोफर्स्ट कर रही है।

चलिए अब चंडीगढ़ में अपने घर वापसी करते हैं और इसलिए सेक्टर 10 में सरकारी म्यूज़ियम का एक और दौरा अनिवार्य हो गया, जहां पर बुद्ध की गांधार प्रतिमाएं भी प्रदर्शित हैं - जिन्हें भारत आज़ाद होने पर लाहौर संग्रहालय के साथ आधा-आधा बांटा गया - सिर्फ यह देखने को कि क्या बदलाव की बयार देश के इस हिस्से तक पहुंची है या नहीं। आप अब भी वहां रखे रजिस्टर में अपना नाम लिखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सचिवालय में किसी नौकरशाह से मिलने जाने पर–मानो प्रवेश के लिए संग्रहालय का टिकट काफी न हो। संग्रहालय अभी भी सुनसान है। मिनिएचर गैलरी में रखी कुछ चीज़ों को हटा दिया गया है क्योंकि छत की मरम्मत हो रही है, लेकिन वह काम रुका हुआ है क्योंकि ऐसा लगता है कि फंड खत्म हो गया।

जैसा कि ला-कॉर्बुज़िए ने कभी कहा होगा... ‘जितना ज़्यादा कुछ चीज़ें बदलती हैं, उतनी ही कुछ दूसरी चीज़ें जस की तस रहती हैं।’

प्रेरणा

पात्रता का अदृश्य विधान

बहुत पुराने समय की बात है। एक समृद्ध और सुव्यवस्थित राज्य में न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसके दरबार में एक ऐसा मंत्री था जिसकी विद्वत्ता और संयम की चर्चा दूर-दूर तक होती थी। लोग कहते थे कि वह केवल राजकार्य ही नहीं संभालता, बल्कि भीतर से साधक भी है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मंत्र-जप करता, ध्यान में बैठता और फिर राजकाज में लग जाता। राजा यह सब देखता था, पर उसके मन में एक जिज्ञासा बार-बार सिर उठाती रहती थी कि क्या मंत्र-जप सचमुच सबके लिए समान रूप से फलदायी होता है या इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है।

एक दिन राजा ने सभा समाप्त होने के बाद मंत्री से यही प्रश्न पूछ लिया। मंत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि मंत्र-शक्ति सब पर समान रूप से काम नहीं करती, वह पात्रता देखकर ही फल देती है। राजा को यह बात कुछ रहस्यमय लगी। उसने कारण जानना चाहा, पर मंत्री ने केवल इतना कहा कि कुछ सत्य अनुभव से ही समझे जा सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई, पर उसने धैर्य रखा।

कुछ दिन बीते। मंत्री ने निश्चय किया कि अब राजा को उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए। एक दिन वह राजा को महल के एक शांत कक्ष में ले गया। वहां उसने पास के गांव से एक साधारण से बालक को बुलवाया, जो न राजा को पहचानता था न मंत्री को। बालक सहज और भोला था। मंत्री ने उसे स्नेह से पास बुलाकर कहा कि यह व्यक्ति मुझे रोज परेशान करता है, तुम इसे एक थप्पड़ मार दो। बालक ने यह सुनकर असमंजस से मंत्री की ओर देखा। उसे बात अनुचित लगी, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा और आदेश का पालन नहीं किया।

राजा यह दृश्य ध्यान से देख रहा था। उसे बालक का व्यवहार अच्छा लगा। तभी मंत्री ने आंखों ही आंखों में राजा से संकेत किया। राजा ने उसी बालक को आदेश दिया कि मंत्री को थप्पड़ मारो। इस बार बालक ने तनिक भी देर नहीं की और तुरंत आज्ञा का पालन कर दिया। मंत्री के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया, वह शांत भाव से खड़ा रहा। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि एक ही बालक ने दो आदेशों पर इतना भिन्न आचरण क्यों किया।

तब मंत्री ने कहा, महाराज, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार इस बालक ने केवल उसी का आदेश माना जिसे वह वास्तविक अधिकारी समझता था, उसी प्रकार मंत्र-शक्ति भी केवल अधिकारी साधक की पुकार सुनती है। मंत्र शब्दों का खेल नहीं, चेतना का अनुशासन है। जो व्यक्ति भीतर से शुद्ध नहीं, उसका जप भी केवल ध्वनि बनकर रह जाता है। पर जो विनम्र, करुणामय और संयमी है, उसके लिए वही मंत्र जीवित शक्ति बन जाता है।

मंत्री ने समझाया कि संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, वे अंधी नहीं होतीं। वे मनुष्य के भाव, उद्देश्य और आचरण को परखती हैं। जैसे सूर्य सब पर समान प्रकाश डालता है, पर कमल ही खिलता है और पत्थर वैसे ही पड़ा रहता है। वर्षा सब जगह होती है, पर उपजाऊ भूमि ही फसल देती है। उसी तरह मंत्र भी उसी हृदय में फलता है जहां श्रद्धा, विवेक और परोपकार की भूमि तैयार हो। राजा यह सुनकर गंभीर हो गया। उसने स्वीकार किया कि वह अब तक मंत्र को केवल चमत्कार की दृष्टि से देखता था। मंत्री ने आगे कहा कि सच्ची साधना पहले मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाती है। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार और लोभ से भरा है, वह यदि हजारों बार भी जप करे तो भी उसका जीवन नहीं बदलेगा। पर जो अपने दोषों से लड़ता है, दूसरों के दुख को समझता है, उसके लिए थोड़ी सी साधना भी बहुत फल देती है। राजा के मन में अनेक प्रश्न उमड़ रहे थे। उसने पूछा कि फिर लोग मंत्रों का दुरुपयोग क्यों करते हैं। मंत्री ने उत्तर दिया कि क्योंकि वे शक्ति तो चाहते हैं, पर पात्रता अर्जित नहीं करना चाहते। आसान रास्ता सबको अच्छा लगता है, पर साधना धैर्य मांगती है। शक्ति जब अयोग्य हाथों में जाती है तो वह कल्याण के स्थान पर विनाश लाती है। इसलिए प्रकृति ने एक अदृश्य विधान बनाया है कि वास्तविक शक्ति केवल योग्य व्यक्ति तक ही पहुंचे। मंत्री की बातें सुनकर राजा को अपने जीवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं। उसने देखा कि जिन लोगों ने केवल बाहरी दिखावे से सफलता पाई, वे भीतर से अशांत रहे, जबकि सरल और सच्चे लोग धीरे-धीरे मजबूत होते गए। उसे लगा जैसे आज उसके सामने जीवन का गहरा रहस्य खुल गया हो। उसने मंत्री से कहा कि अब वह भी केवल जिज्ञासु नहीं, साधक बनना चाहता है।

मंत्री ने बताया कि पात्रता कोई जन्म से नहीं मिलती, इसे रोज के आचरण से गढ़ना पड़ता है। सत्य बोलना, अन्याय न करना, जरूरतमंद की सहायता करना, मन को नियंत्रित रखना—यही असली साधना है। मंत्र तो इस साधना को दिशा देने वाला दीपक मात्र है। दीपक तभी प्रकाश देता है जब उसमें तेल और बाती दोनों हों। इसी प्रकार मंत्र तभी फल देता है जब उसमें शुद्ध जीवन का ईंधन हो।

उस दिन के बाद राजा के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह निर्णयों में अधिक संवेदनशील हो गया, प्रजा की पीड़ा को सुनने लगा। दरबार में भी मंत्री की कथा फैल गई। लोग समझने लगे कि शक्ति मांगने से पहले स्वयं को योग्य बनाना जरूरी है। धीरे-धीरे राज्य में यह विश्वास गहरा होता गया कि कोई भी वरदान बिना पात्रता के टिक नहीं सकता।

कहते हैं, वर्षों बाद जब वही बालक बड़ा हुआ तो वह राजा का विश्वस्त सेवक बना। वह अक्सर लोगों को बताता कि उस एक घटना ने उसे जीवन भर सिखाया कि आदेश वही निभाए जाते हैं जिनके पीछे सच्चा अधिकार हो। मंत्र-शक्ति भी उसी अधिकार की तरह है—दिखती नहीं, पर सही व्यक्ति के हाथों में संसार बदल देती है।

यह कथा केवल एक राजा और मंत्री की नहीं, हर मनुष्य की है। हम सब किसी न किसी शक्ति की कामना करते हैं, पर भूल जाते हैं कि असली तैयारी भीतर करनी होती है। पात्रता का यह अदृश्य विधान सदा से काम करता आया है और करता रहेगा। जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन स्वयं एक मंत्र बन जाता है।

कॉरपोरेट छाया में सिकुड़ती हिंदी की आत्मा

आज हिंदी जितनी चमकदार दिखाई दे रही है, उतनी भीतर से आश्वस्त नहीं है। मंचों पर सम्मान, पदों पर नियुक्तियां और पुरस्कारों की झड़ी को देखकर लगता है मानो भाषा का स्वर्णकाल आ गया हो, परंतु यह चमक कई बार उस रोशनी जैसी है जो बाहर से आंखों को चकाचौंध कर देती है और भीतर अंधेरा छोड़ देती है। विश्वविद्यालयों में हिंदी के प्रोफेसरों का कुलपति बनना, सरकारी कार्यालयों में हिंदी सप्ताह मनाया जाना और कॉरपोरेट जगत में हिंदी के विज्ञापन दिखना, ये सब देखने में प्रगति के संकेत लगते हैं, किंतु इनके पीछे छिपा यथार्थ उतना सुखद नहीं है। भाषा का विकास यदि केवल पद और समारोहों तक सीमित हो जाए तो वह एक ऐसे शरीर जैसा हो जाता है जिसका सिर तो बड़ा होता जाता है पर हाथ पैर निर्बल पड़ते जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक जीवन में जिस तरह की आक्रामक और कटु भाषा हिंदी में सुनाई देने लगी है, वह चिंता का विषय है। चुनावी बहसों, टीवी चर्चाओं और सोशल मीडिया पर शब्दों की मर्यादा लगातार टूट रही है। हैरानी की बात यह है कि यह हिंसक तेवर अधिकतर हिंदी के माध्यम से ही प्रकट हो रहा है। भाषा जो संवाद और संवेदना का माध्यम होनी चाहिए, वह कई बार धमकी और दमन का औजार बनती दिखती है। कवि मंगलेश डबराल ने इस प्रवृत्ति को बहुत पहले पहचान लिया था जब उन्होंने अपनी कविताओं में भाषा के भीतर फैलती क्रूरता की ओर संकेत किया। उनके बाद कई रचनाकारों ने महसूस किया कि सत्ता के करीब पहुंचते ही भाषा का रंग बदलने लगता है, वह जनता के दुख से दूर और ताकत के पक्ष में खड़ी हो जाती है।

यह दोहरा आचरण नया नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजी के संदर्भ में जो बात कही थी कि भीतर तत्व न झूठी तेजी, वह आज हिंदी पर भी लागू होती है। बाहर से तेज प्रगति का शोर है, पर भीतर मौलिक सृजन, गहन चिंतन और जनपक्षधर आवाजें कमजोर पड़ रही हैं। कॉरपोरेट संस्कृति ने भाषा को उपभोक्ता वस्तु में बदल दिया है। विज्ञापनों की चमकदार हिंदी, बाजार की जरूरतों के अनुसार ढली हुई हिंदी, और प्रबंधन की बैठकों में इस्तेमाल होने वाली आधी अंग्रेजी मिली हिंदी, यही अब मुख्यधारा बनती जा रही है। इस प्रक्रिया में वह हिंदी पीछे छूट रही है जो गांव, कस्बों और आम लोगों के जीवन से निकली थी।

नागार्जुन ने बहुत पहले चेताया था कि साहित्यकार की प्रतिष्ठा उस जनता की उन्नति से जुड़ी होती है जिसकी भाषा में वह लिखता है। आज स्थिति उलटी दिखाई देती है। जनता आर्थिक दबावों में घिरी है और साहित्यकार पुरस्कार समारोहों की चकाचौंध में व्यस्त है। जिस तरह साधारण नागरिक को अधिकार संपन्न व्यक्ति बनाने के बजाय केवल योजनाओं का लाभार्थी बना दिया गया है, उसी तरह लेखक को भी स्वाभिमानी रचनाकार के स्थान पर आयोजनों का अतिथि बना दिया गया है। जब लेखक सत्ता और कॉरपोरेट अनुदानों पर निर्भर हो जाएगा तो उसकी भाषा स्वाभाविक रूप से प्रश्न पूछने की ताकत खो देगी।

स्वाधीनता आंदोलन के समय हिंदी ने जो भूमिका निभाई थी, वह आज भी प्रेरणा देती है। तब यह भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि प्रतिरोध का औजार थी। प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, महादेवी और अनेक रचनाकारों ने हिंदी को जनता की आवाज बनाया। बाद के दौर में प्रगतिशील साहित्यकारों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। परंतु उदारीकरण के बाद का समय अलग तरह का दबाव लेकर आया। बाजार ने संस्कृति को भी उत्पाद में बदल दिया और भाषा उसके प्रचार का माध्यम बन गई। बड़े प्रकाशन घर, प्रायोजित साहित्य उत्सव और मीडिया की पसंद, इन सबने मिलकर एक ऐसी हिंदी गढ़ी जो चमकदार तो है पर धारहीन है।

कॉरपोरेट दुनिया के लिए भाषा का मूल्य उसकी बिक्री क्षमता से तय होता है। जो शब्द उपभोक्ता को आकर्षित करे, वही सही माना जाता है। इसलिए हिंदी में सरलता के नाम पर सतहीपन बढ़ा, गंभीरता को बोझ समझा जाने लगा। कार्यालयों में अंग्रेजी का दबदबा कायम रहा और हिंदी को सजावटी भूमिका मिली। अनेक कंपनियों में हिंदी दिवस तो मनाया जाता है, पर कामकाज की वास्तविक भाषा अंग्रेजी ही रहती है। यह विरोधाभास बताता है कि सम्मान प्रतीकात्मक है, वास्तविक अधिकार नहीं। भाषा पर हमला केवल बाजार से नहीं, राजनीति से भी हुआ है। चुनावी भाषणों में हिंदी का प्रयोग भीड़ को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है। तर्क की जगह नारे और संवाद की जगह आरोप सुनाई देते हैं। इस प्रवृत्ति से हिंदी की सार्वजनिक छवि बिगड़ी है। युवा पीढ़ी गंभीर विमर्श के लिए अंग्रेजी की ओर देखती है और हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा मानने लगती है। यह स्थिति किसी भी जीवित भाषा के लिए खतरनाक है।

दुनिया की कई भाषाओं ने ऐसे संकट झेले हैं। अंग्रेजी पर जब बीबीसी के माध्यम से मानकीकरण का दबाव पड़ा तो राल्फ फाक्स जैसे चिंतकों ने चेतावनी दी थी कि भाषा को लोकजीवन से काट दिया जाएगा। हिंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एकाधिकारी प्रवृत्तियां भाषा को नियंत्रित करना चाहती हैं, ताकि विचारों की विविधता सीमित हो सके। यदि भाषा स्वतंत्र नहीं रहेगी तो लोकतंत्र भी कमजोर पड़ेगा। हिंदी को बचाने का रास्ता केवल सरकारी आदेशों से नहीं निकलेगा। जरूरी है कि शिक्षा व्यवस्था में हिंदी को ज्ञान की गंभीर भाषा के रूप में स्थापित किया जाए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाजशास्त्र और दर्शन की मौलिक किताबें हिंदी में लिखी जाएं, अनुवाद नहीं बल्कि सृजन हो। मीडिया को भी सनसनी के बजाय संवेदनशील भाषा को महत्व देना होगा। साहित्यकारों को समारोहों की चमक से बाहर निकलकर जनता के बीच लौटना होगा, वहीं से भाषा को नई ऊर्जा मिलेगी।

अभियान

पीले आकाश के नीचे : वसंत पंचमी और जीवन की पुनर्रचना

भारतीय सभ्यता ने समय को केवल घड़ी की सुई से नहीं, ऋतुओं की धड़कन से मापा है। जब माघ की ठंड कुछ नरम पड़ती है, हवा में गुनगुनी मिठास घुलने लगती है और धरती पर पीले रंग की हल्की-सी मुस्कान फैलती है, तब वसंत पंचमी का पर्व आता है। यह दिन महज एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ मनुष्य के नये अनुबंध का क्षण है। शीत की जड़ता टूटती है, पेड़ों पर नयी कोंपलें फूटती हैं, सरसों के खेत सोने की तरह दमक उठते हैं और मनुष्य के भीतर भी किसी अदृश्य वीणा के तार झनझना उठते हैं। भारतीय समाज ने इस प्राकृतिक बदलाव को केवल मौसम का परिवर्तन नहीं माना, बल्कि उसे संस्कृति, ज्ञान और कला के उत्सव में बदल दिया।

वसंत पंचमी का अर्थ समझने के लिए भारतीय जीवन दृष्टि को समझना जरूरी है। यहां ऋतुएं केवल मौसम नहीं, मनुष्य की आंतरिक अवस्थाओं की प्रतीक हैं। ग्रीष्म संघर्ष का, वर्षा करुणा का, शरद शांति का और वसंत सृजन का प्रतीक माना गया। इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा गया—ऐसा राजा जो कठोरता से नहीं, सौंदर्य से शासन करता है। किसान के लिए यह समय सबसे भरोसे का होता है। महीनों की मेहनत के बाद खेत आश्वासन देने लगते हैं कि फसल सफल होगी। यही भरोसा पूरे समाज के मन में उतरता है। वसंत पंचमी दरअसल इसी भरोसे का सार्वजनिक उत्सव है—प्रकृति और मनुष्य के बीच विश्वास का हस्ताक्षर।

भारतीय परंपरा ने इस प्राकृतिक आनंद को ज्ञान की आराधना से जोड़ दिया। इसलिए वसंत पंचमी देवी सरस्वती का पर्व बन गई। सरस्वती केवल किसी मूर्ति का नाम नहीं, चेतना के उस प्रकाश का रूप हैं जो मनुष्य को पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाता है। इस दिन विद्यालयों में, घरों में, गुरुकुलों में पुस्तकों, लेखनी और वाद्ययंत्रों की पूजा होती है। छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है। यह परंपरा बताती है कि भारत में शिक्षा कभी केवल रोजगार का माध्यम नहीं रही, बल्कि जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने का संस्कार रही है। अक्षर यहां ब्रह्म के समान पवित्र माने गए, क्योंकि शब्द ही मनुष्य को सभ्य बनाते हैं।

पीला रंग इस पर्व की पहचान है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, घरों को पीले फूलों से सजाते हैं, भोजन में केसरिया व्यंजन बनते हैं। यह रंग केवल सौंदर्य नहीं, एक दर्शन है। पीला सूर्य का, ऊर्जा का, जागरण का रंग है। मनोविज्ञान भी मानता है कि यह रंग मन में उत्साह और स्पष्टता जगाता है। वसंत पंचमी पर पूरा समाज जैसे एक ही रंग में रंगकर सामूहिक आशा का दृश्य बन जाता है। यह संदेश है कि जीवन में अंधकार कितना भी हो, भीतर एक पीली किरण हमेशा बची रहती है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में यह पर्व भिन्न-भिन्न रूपों में मनाया जाता है। कहीं सरस्वती पूजा मुख्य है, कहीं पतंगों से भरा आकाश उत्सव का केंद्र बन जाता है। बंगाल में कलाकार और विद्यार्थी इस दिन को वर्ष का सबसे पवित्र दिन मानते हैं। उत्तर भारत में घरों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक हवन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गूंज रहती है। पंजाब और हरियाणा में सरसों के खेतों के बीच लोकगीत गूंजते हैं। गुजरात और राजस्थान में पतंगों की रंगीन लड़ाई होती है। पर इन सब विविधताओं के भीतर एक ही भाव बहता है—नये जीवन का स्वागत।

वसंत पंचमी केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पर्व भी है। लंबी सर्दी के बाद मनुष्य के भीतर जो सुस्ती भर जाती है, यह उत्सव उसे तोड़ता है। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं, गीत गाते हैं, हंसते हैं। सामूहिकता की यह भावना समाज को जोड़ती है। आज के समय में जब अकेलापन और अवसाद बढ़ रहे हैं, ऐसे पर्व मानसिक स्वास्थ्य के लिए औषधि जैसे हैं। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर मन भी संतुलित होता है। शायद हमारे पूर्वजों ने यह गहरी बात अनुभव से समझ ली थी।

इस पर्व का साहित्य और कला से रिश्ता अत्यंत पुराना है। कालिदास से लेकर आधुनिक कवियों तक, वसंत सबसे प्रिय विषय रहा है। संस्कृत काव्यों में वसंत को कामदेव का सहचर कहा गया, भक्ति साहित्य में इसे ईश्वर की मुस्कान माना गया और आधुनिक कविता में यह मनुष्य की आजादी का रूपक बना। शास्त्रीय संगीत में वसंत रागों का गायन, नृत्य में ऋतु आधारित मुद्राएं, चित्रकला में पीले और हरे रंगों का उत्सव—ये सब बताते हैं कि भारतीय कला मूलतः प्रकृति की संतान है। जब कलाकार वसंत को रचता है, तो वह दरअसल अपने भीतर के वसंत को खोजता है।

खानपान भी इस पर्व की सांस्कृतिक भाषा है। केसरिया खीर, मीठे चावल, बूंदी, हलवा—इन व्यंजनों में केवल स्वाद नहीं, प्रतीक छिपे हैं। मिठास जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि का संकेत है। सामूहिक भोज यह बताता है कि आनंद अकेले नहीं, मिल-बांटकर सुंदर बनता है। गांवों में आज भी इस दिन लोग एक-दूसरे के घर पकवान भेजते हैं। यह परंपरा रिश्तों की गर्मी को बचाए रखती है।

वसंत पंचमी का एक और पक्ष है—पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं। पेड़-पौधे, पक्षी, नदियां—ये सब हमारे उत्सव के सहभागी हैं। जब हम सरसों के पीले फूलों को पूजते हैं, तो दरअसल धरती के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज जब विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वसंत पंचमी एक मौन चेतावनी भी है कि यदि प्रकृति रूठ गई तो हमारे सारे उत्सव सूने पड़ जाएंगे।

समय के साथ पर्वों के रूप बदलते हैं, पर आत्मा बनी रहती है। आधुनिक शहरों में भी वसंत पंचमी नये अर्थ ग्रहण कर रही है। स्कूलों में कला मेले, पुस्तक दान, संगीत कार्यशालाएं, पर्यावरण अभियान—ये सब इस पर्व को समकालीन बनाते हैं। डिजिटल युग के बीच यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली ज्ञान केवल स्क्रीन पर नहीं, अनुभव में बसता है। किताब की खुशबू, वीणा की ध्वनि और फूलों की सुगंध—ये मनुष्य को भीतर से जीवित रखते हैं।

वसंत पंचमी दरअसल जीवन को देखने का एक तरीका है। यह सिखाती है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। जैसे प्रकृति हर साल पुरानी पत्तियां गिराकर नये पत्ते धारण करती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर की जड़ता छोड़नी चाहिए। ज्ञान वही है जो हमें नया बनाता है, कला वही है जो हमें संवेदनशील बनाती है और धर्म वही है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है। इस पर्व का गूढ़ संदेश यही है।

आज जब समाज अनेक तनावों से घिरा है, तब वसंत पंचमी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। यह हमें कठोरता के बीच कोमलता बचाने की कला सिखाती है। याद दिलाती है कि जीवन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, उत्सव भी है। बच्चों की मुस्कान, छात्रों की जिज्ञासा, कलाकार की साधना और किसान की उम्मीद—ये सब मिलकर वसंत का वास्तविक अर्थ रचते हैं।

अंततः वसंत पंचमी मनुष्य और प्रकृति के सह-अस्तित्व का गीत है। यह बताती है कि ज्ञान, कला और पर्यावरण—तीनों का संतुलन ही सभ्यता को सुंदर बनाता है। जब तक धरती पर पीले फूल खिलते रहेंगे, जब तक मनुष्य अक्षर से प्रेम करता रहेगा, तब तक वसंत जीवित रहेगा। और जिस दिन मनुष्य के भीतर से वसंत खो गया, उस दिन सारे उत्सव अर्थहीन हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम इस पर्व को केवल परंपरा की तरह नहीं, जीवन दृष्टि की तरह जिएं—ताकि हमारे भीतर भी हमेशा एक छोटा-सा वसंत खिलता रहे।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

आत्मनिर्भर गुजरात के निर्माण में साप्ति की उल्लेखनीय भूमिका दिसंबर-2025 तक संस्थान से 674 उम्मीदवार स्नातक हुए

▸▸ 'साप्ति' के माध्यम से ध्रांगध्रा के युवक अक्षय पिलाणी बने शिल्पकला में पारंगत, प्रतिमाह करते हैं 40,000 रुपए की कमाई

▸▸ शिल्पकला क्षेत्र में कौशल विकास को वेग दे रहा है स्टोन आर्टिजन पार्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (साप्ति)

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र का अनुकरण करते हुए गुजरात सरकार द्वारा स्थापित स्टोन आर्टिजन पार्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी 'एसएपीटीआई/साप्ति' राज्य के पत्थर शिल्पकला क्षेत्र में कौशल विकास को वेग दे रहा है। यह संस्थान पत्थर कला की मूल्यवान विरासत को बनाए रखने के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। दिसंबर-2025 तक कुल 674 उम्मीदवार इस संस्थान से स्नातक हुए हैं।

गुजरात में अंबाजी तथा ध्रांगध्रा में हैं आर्टिजन पार्क

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार के खान एवं उद्योग विभाग तथा भूविज्ञान एवं खनन कार्य आयुक्त कार्यालय-गांधीनगर द्वारा स्थापित साप्ति राज्य के शिल्पकला उद्योग की संभावनाओं का उपयोग करता है और पत्थर कला तथा शिल्प-स्थापत्य की मूल्यवान विरासत को आगे बढ़ा रहा है। राज्य में अंबाजी (बनासकाँठा जिला) और ध्रांगध्रा (सुरेन्द्रनगर जिला) में – दो आर्टिजन पार्क्स की स्थापना की गई है। उत्तर गुजरात में स्थित साप्ति-अंबाजी संगमरमर के शिल्पों पर ध्यान केन्द्रित करता है, जबकि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित साप्ति-ध्रांगध्रा रेत-पत्थर के शिल्पों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में आज साप्ति जैसा संस्थान सांस्कृतिक धरोहर को रोजगार के अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

2022 से 2025 के दौरान साप्ति के दोनों केन्द्रों पर 1,082 उम्मीदवारों का पंजीकरण हुआ

2022 से 2025 के दौरान साप्ति के दोनों केन्द्रों पर 1,082 उम्मीदवारों का पंजीकरण हुआ है। 26 दिसंबर, 2025 तक कुल 674 उम्मीदवार इस संस्थान से स्नातक हुए हैं, जिनमें अंबाजी केन्द्र के 307 उम्मीदवार तथा ध्रांगध्रा केन्द्र के 367 उम्मीदवार शामिल हैं। ये आँकड़े गुजरात के शिल्प उद्योग के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण करने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाते हैं।

साप्ति के माध्यम से ध्रांगध्रा के युवक अक्षय पिलाणी बने शिल्पकला में पारंग, प्रतिमाह करते हैं 40,000 रुपए की कमाई

सुरेन्द्रनगर जिले की ध्रांगध्रा तहसील के चुली गाँव के युवक अक्षय पिलाणी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद भारतीय पुलिस या सेना में जुड़ना चाहते थे। इस बीच उन्हें साप्ति-ध्रांगध्रा के माध्यम से पत्थर हस्तकला तथा डिजाइन में कॅरियर के अवसर के बारे में जानने को मिला। स्टोन क्राफ्ट तथा डिजाइन कोर्स में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उनके कॅरियर को नया मोड़ मिला। ढाँचागत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से अक्षय ने पत्थर की नक्काशी/उत्कीर्णन कला, चित्रकारी, प्रोडक्ट डिजाइन तथा आधुनिक मशीनरी के उपयोग के साथ परंपरागत उत्कीर्णन कला की तकनीक में भी निपुणता प्राप्त की। कार्यक्रम में प्रशिक्षण के अतिरिक्त; उन्होंने सम्बद्ध उद्योग के व्यवसायियों के साथ काम करके व्यावहारिक अनुभव तो प्राप्त किया ही, साथ ही वित्तीय सहायता भी प्राप्त की। किसान परिवार से आने वाले अक्षय पिलाणी ने आज एक विशेषज्ञ कारीगर के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। उन्होंने चंडीगढ़ में दो बड़े स्टोन कार्विंग (पत्थर पर उत्कीर्णन) प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। आज वे हर महीने लगभग 40,000 रुपए कमाते हैं। उनकी इस यात्रा ने अन्य युवाओं को भी शिल्पकला के प्रति आकर्षित किया है।

सदियों पुरानी शिल्पकला को बनाए रखने में साप्ति की उल्लेखनीय भूमिका

साप्ति का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, नवीनता तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन देते हुए देश की शिल्पकला को मजबूत बनाकर उसका जतन करना है। रोजगार सृजन के अलावा; साप्ति गुजरात की सदियों पुरानी पत्थर कला एवं स्थापत्य की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंपरागत तकनीकों, आधुनिक संसाधनों और वैश्विक डिजाइन के समन्वय के साथ यह संस्थान शिल्पकला की विरासत को पुनर्जीवित करने के साथ उसे आधुनिक बाजारों के अनुकूल बना रहा है।

कांदिवली कार शेड में प्रवेश एवं निकास के निलंबन के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त

(जीएनएस)। कांदिवली कार शेड में प्रवेश एवं निकास के निलंबन तथा कांदिवली–मालाड के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइन पर लगाए गए गति प्रतिबंधों के कारण 20 जनवरी, 2026 को कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी। ब्लॉक के कारण प्रभावित उपनगरीय ट्रेनों की सूची अनुलग्नक–I में दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित उपनगरीय स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों पर ध्यान में रखें और तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

वडोदरा स्टेशन पर रेल लाइन के ट्रैक स्ट्रक्चर को बनाया गया बेहतर, प्लेटफार्म का भी किया गया विस्तार

(जीएनएस)। वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा वडोदरा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन के ट्रैक स्ट्रक्चर में सुधार के साथ साथ राइडिंग क्वालिटी को बेहतर बनाने के क्रम में इंफ्रा के कई महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए गए है। इसके साथ साथ वडोदरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 को 50 मीटर तक विस्तारित भी कर दिया गया है, जिससे ट्रेनों के ऑपरेशन में सुविधा के साथ साथ प्लेटफार्म पर यात्रियों का मूवमेंट और बेहतर हो सकेगा। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वडोदरा स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन के इंफ्रा के कई महत्वपूर्ण कार्यों को इंजीनियरिंग विभाग के रेलकर्मियों ने अथक प्रयास से महज 25 दिन ब्लॉक लेकर पूर्ण कर लिया। पहले प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन पर लगातार पानी रुक रहा था, जिससे गंदगी फैल रही थी और बार-बार ट्रैक सर्किट फेल हो रहे थे। जिसकी वजह से ट्रेनों की पंक्चुअलिटी पर असर पड़ रहा था। लंबे समय तक ट्रैक पर पानी जमा रहने से रेल ट्रैक के स्लीपर और ट्रैक की बनावट खराब हो रही थी, जिससे ट्रेन परिचालन में संरक्षा प्रभावित हो रही थी। इन कमियों को ठीक करने के लिए वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा मेंटेनेंस और ऑपरेशनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 400 मीटर

लंबी नई वॉटर हाइड्रेंट पाइपलाइन बिछाई गई। सतह और ज़मीन के नीचे के पानी को प्रभावी ढंग से निकालने के लिए लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 के बीच 300 मीटर का एक नया सेंट्रल ड्रेन बनाया गया। इसके अलावा, मौजूदा 380 मीटर सेंट्रल ड्रेन की मरम्मत कर उसे ठीक किया गया है, और उस पर कवर स्क्रीन भी लगाई गई।

इसके अतिरिक्त, सही गिट्टी कुशन को बहाल करने, ड्रेनेज को बेहतर बनाने और खराब गिट्टी को हटाने के लिए लाइन नंबर 3 पर 790 मीटर की डीप स्क्रीनिंग की गई। क्षतिग्रस्त और खराब स्लीपरों को बदलने और ट्रैक की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 790 मीटर का टोटल स्लीपर रिन्यूअल (TSR) किया गया।

सेक्शन को 30 किमी प्रति घंटे की अनुमत गति के लिए उपयुक्त बनाने के लिए ट्रैक ज्योमेट्री को ठीक किया गया है, जिसमें अलाइनमेंट, कैंट और गेज शामिल हैं और कर्व पैरामीटर को फिर से अलाइन किया गया है। इन इंफ्रा कार्यों से प्लेटफार्म नंबर 3 की रेल लाइन के ट्रैक स्ट्रक्चर में सुधार के साथ साथ राइडिंग क्वालिटी भी बेहतर होगी।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने टिकट जांच में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 13 कर्मचारियों को किया सम्मानित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में टिकट जांच के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

इस संबंध में भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भावनगर मंडल के टिकट जांच कर्मी अत्यंत जिम्मेदारी एवं निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये कर्मी न केवल यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने में सहायक हैं, बल्कि रेलवे की आय वृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि भावनगर मंडल द्वारा अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5.09 करोड़ की आय अर्जित की गई है, जबकि मात्र अप्रैल 2025 माह में ही 77.23 लाख की आय दर्ज की गई है।

मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सम्मानित किए गए कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं– श्री आई. बी. मुंशी (आरक्षण पर्यवेक्षक, गांधीग्राम), श्री ध्रुव अमीन (सीनियर सीसी/टीसी, गांधीग्राम), श्री योगेन्द्र सिंह (सीसी/टीसी, जूनागढ़), श्री आर. एम. चौहान (मुख्य वाणिज्य लिपिक, भावनगर), श्री वी. एन. जडेजा (आरक्षण पर्यवेक्षक, जूनागढ़), श्री शैलेष बी. परमार (उप मुख्य टिकट निरीक्षक, गांधीग्राम), श्री अरविंद कुमार गुर्जर (उप मुख्य टिकट निरीक्षक, वेरावल), श्री के. सी. मीणा (मुख्य टिकट निरीक्षक, गांधीग्राम), श्री प्रेम चंद (सीनियर सीसी/टीसी, गांधीग्राम), श्री राजन कुमार सिंह (मुख्य टिकट निरीक्षक, वेरावल), श्री आर. पी. मेघवंशी (मुख्य टिकट संग्राहक, बोटाद), श्री जे. पी. मकवाना (मुख्य टिकट निरीक्षक, बोटाद) एवं श्री अमोद कुमार (सीसी/टीसी, बोटाद)।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी सम्मानित कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

77वें गणतंत्र पर्व 26 जनवरी, 2026 का राज्य स्तरीय समारोह नवगठित वाव-थराद जिले में आयोजित होगा

▸▸ राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में ध्वजारोहण करेंगे तथा परेड की सलामी लेंगे

▸▸ उप मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य राज्य के जिलों में विभिन्न तहसील मुख्यालयों पर फहराएंगे तिरंगा

▸▸ 9 जिलों में

(जीएनएस)। गांधीनगर : 77वें गणतंत्र पर्व 26 जनवरी 2026 का राज्य स्तरीय समारोह नवगठित वाव-थराद जिले में आयोजित होगा।

राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में वाव-थराद जिला मुख्यालय मालपुर में नए कोर्ट के सामने स्थित हेलीपैड मैदान में गणतंत्र पर्व पर सुबह 9 बजे राष्ट्रध्वज फहरा कर ध्वज वंदन कराएंगे और परेड मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुलिस बल द्वारा विभिन्न निदर्शन भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से राष्ट्रीय पर्वों का राज्य स्तरीय समारोह अलग-अलग जिलों में जन भागीदारी से आयोजित करने की शुरू कराई गई नूतन परंपरा के अनुसार 77वें गणतंत्र पर्व का राज्य स्तरीय समारोह नवगठित वाव-थराद जिले में आयोजित होने वाला है।

यह राष्ट्रीय पर्व राज्य के विभिन्न जिलों में तहसील मुख्यालयों पर आयोजित होगा। इसमें उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी अहमदाबाद में मकरबा क्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा; राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य सम्बद्ध जिलों के मुख्यालयों पर गणतंत्र पर्व समारोह में उपस्थित रहकर ध्वजारोहण करेंगे।

राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा इस संदर्भ में घोषित की गई सूची के अनुसार केबिनेट स्तरीय मंत्रियों में वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई नवसारी जिले के चीखली में, कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी राजकोट जिले के जेतपुर में, ऊर्जा मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल गांधीनगर जिले के माणसा में, श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री कुँवरजीभाई बावळिया पोरबंदर जिले के राणावाव में, आदिजाति विकास मंत्री श्री नरेशभाई पटेल वलसाड जिले के उमरगाम में, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया दाहोद जिले के गोविंद गुरु-लींबडी में, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमनभाई वाजा साबरकाँठा जिले के हिंमतनगर में तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी खेडा जिले के ठासरा में तिरंगा फहराएंगे।

राज्य स्तरीय मंत्री जिन जिलों में गणतंत्र पर्व के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण करेंगे; उनमें जल संसाधन राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल नर्मदा जिले के एकतानगर (केवडिया) में, महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील छोटा उदेपुर जिले के बोडेली में, मत्स्योद्योग राज्य मंत्री श्री परसोत्तम सोलंकी गीर-सोमनाथ जिले के तालाला में, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री कांतिभाई अमृतिया कच्छ जिले के भुज में, कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा पंचमहाल जिले के हालोल में, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला सुरेन्द्रनगर जिले के वढवाण में, विधि राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया भावनगर जिले के वलभीपुर में, परिवहन राज्य मंत्री श्री प्रवीणभाई माळी मेहसाणा जिले के विसनगर में, खेल राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित डांग जिले के आहवा में, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांग अमरेली जिले के खांभा में, वित्त राज्य मंत्री श्री कमलेशभाई पटेल वडोदरा जिले के वाघोडिया में, राजस्व राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा आणंद जिले के खंभात में, आदिजाति विकास राज्य मंत्री श्री पी. सी. बरंडा महिसागर जिले के कडाणा में, कुटीर उद्योग राज्य मंत्री श्री स्वरूपजी ठाकोर पाटण जिले के शंखेश्वर में तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा बोटाद जिले के गढडा में तिरंगा फहराएंगे।

राज्य के जिन 9 जिलों के तहसील मुख्यालयों पर जिला कलेक्टरों द्वारा ध्वजारोहण होने वाला है; उनमें अरवल्ली जिले के मेघरज में, बनासकाँठा के ओगड में, भरूच जिले के आमोद में, देवभूमि द्वारका जिले के भाणवड में, जामनगर जिले के कालावड में, जूनागढ जिले के केशोद में, मोरबी जिले के टंकारा में, सूरत जिले के मांडवी में तथा तापी जिले के उच्छल में सम्बद्ध जिला कलेक्टर तिरंगा झंडा फहराएंगे।

स्मार्ट शहर के लिए स्मार्ट उपाय : सीसीटीवी + एआई = आवारा गाय को भीड़ में चिह्नित कर उसके मालिक की पहचान उजागर करेगा

▸▸ फिंगर प्रिंट की तरह गाय की नाक है उसकी यूनिक बायोमेट्रिक आईडी : नाक की रचना, आँखों तथा चेहरे को स्कैन करने वाली टेक्नोलॉजी

▸▸ अहमदाबाद महानगर पालिका के लिए पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी, एजेंसी द्वारा एआई मॉडल निर्माण पर कार्य शुरू

▸▸ गुजरात के शहरों के सर्वांगीण विकास का विजन, एआई टेक्नोलॉजी से स्मार्ट गवर्नेंस की ओर राज्य सरकार के बढ़ते कदम

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए राज्य सरकार आधुनिक टेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गांधीनगर में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने के बाद इस टेक्नोलॉजी को राज्य के शासन में समाविष्ट कर नागरिक सेवा वितरण को समृद्ध बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) क्षेत्र के दायरे में आने वाली समस्या के लिए एक महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में आवारा पशुओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान आसान बनेगा। अहमदाबाद में भटकती-आवारा गायों के कारण कई बार यातायात समस्या देखने को मिलती है। हाल में अहमदाबाद मनपा की टीम सीसीटीवी कैमरा की सहायता से अलग-अलग क्षेत्रों में आवारा गायों की तसवीर खींचने के बाद उसमें लगी माइक्रो चिप तथा आरएफआईडी टैग के आधार पर गाय को चिह्नित करती है। यह प्रक्रिया मैन्युअल होने के कारण इसमें समय एवं ऊर्जा का काफी व्यय होता है। इस कार्य को तेज बनाने तथा समय एवं ऊर्जा का व्यय घटाने के लिए अब एआई टेक्नोलॉजी को इस कार्य में शामिल करने के प्रयास शुरू किए गए हैं।

इस समस्या के निवारण के उद्देश्य से गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा एक एजेंसी को एआई मॉडल बनाने का कार्य सौंपा गया है। एजेंसी ने डीप लर्निंग मॉडल द्वारा इस समस्या के निराकरण के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं और उनके आधार पर एजेंसी संचालन समिति के समक्ष उनके द्वारा तैयार किया गया मॉडल शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी। एजेंसी सीसीटीवी कैमरा द्वारा ली जाने वाली तसवीरों को एआई मॉडल के साथ एकीकृत कर रियल टाइम में गाय तथा उसके मालिक की पहचान करने वाला एआई मॉडल तैयार कर रही है।

एजेंसी का प्रस्तावित एआई मॉडल कैसे काम करेगा ?

एजेंसी ने कम्प्यूटर विजन तथा डीप लर्निंग एआई मॉडल द्वारा इस समस्या का समाधन सुझाया है। इस मॉडल अंतर्गत एआई गाय के चेहरे को स्कैन करेगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पहचान गाय की नाक के आधार पर होगी। जिस प्रकार हर व्यक्ति की फिंगर प्रिंट अलग-अलग होती है, उसी प्रकार हर गाय के नाक का डिजाइन अलग-अलग होता है। इसके अलावा; गाय की आँखों व चेहरे पर कोई दाग या निशान हो, तो उसे भी स्कैन किया जाएगा। उसके आधार पर एआई मॉडल उस गाय को भीड़ में चिह्नित कर लेगा और डेटाबेस के साथ मैच कर गाय के मालिक का विवरण भी प्रस्तुत कर देगा। हाल में अहमदाबाद में लगभग 1 लाख 10 हजार गायों में आरएफआईडी टैग तथा माइक्रो चिप लगी हुई हैं। उसका डेटाबेस अहमदाबाद मनपा द्वारा संरक्षित किया जाता है। शहर में 130 जंक्शन पर कैमरा द्वारा आवारा गायों की तसवीरें ली जाती हैं। एआई आधारित यह सॉल्यूशन यदि कारगर सिद्ध होगा, तो मनपा क्षेत्र में आवारा गायों के कारण होने वाली यातायात व अन्य समस्याओं के शीघ्र निवारण में सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से सरकार का आवारा गायों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोककर सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने और डेटा आधारित निरीक्षण व्यवस्था को प्रस्थापित करने का उद्देश्य है।

पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली एवं बोरीवली के बीच छठी लाइन का कमीशन किया गया

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सफलतापूर्वक पूर्ण

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने मुंबई उपनगरीय खंड में कांदिवली एवं बोरीवली के बीच 3.210 किलोमीटर लंबी छठी लाइन का सफलतापूर्वक कमीशन कर एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि 18 जनवरी, 2026 को रेल संरक्षा आयुक्त (पश्चिम परिमंडल) द्वारा सफल निरीक्षण के उपरांत प्राप्त हुई।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक् प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रेल संरक्षा आयुक्त (पश्चिम परिमंडल) श्री ई. श्रीनिवास ने कांदिवली एवं बोरीवली के बीच नव निर्मित छठी लाइन खंड का विस्तृत निरीक्षण किया। इसके पश्चात गति परीक्षण किए गए, जिसके बाद इस खंड को नियमित रेल परिचालन के लिए अधिकृत किया गया।

कांदिवली–बोरीवली खंड बांद्रा टर्मिनस एवं बोरीवली के बीच परियोजना के फेज-I का अंतिम हिस्सा है। इससे पूर्व खार रोड–गोरेगांव खंड का कमीशन नवंबर 2023 में तथा गोरेगांव–कांदिवली खंड का कमीशन अक्टूबर 2024 में किया जा चुका है। अंतिम खंड का कार्य 18 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 के बीच मात्र 30 दिनों की सुव्यवस्थित समय-सीमा में पूर्ण किया गया, जो पश्चिम रेलवे के विभिन्न विभागों के बीच बेहतर प्लानिंग, चौबीसों घंटे कार्य निष्पादन एवं

उत्कृष्ट समन्वय को दर्शाता है।

इस कमीशनिंग कार्य में बड़े पैमाने पर ट्रैक पुनर्संरेखण, पुलों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिक सिगनलिंग का एकीकरण, विद्युतीकरण कार्य, भूमि अधिग्रहण आदि शामिल थे। उपनगरीय यात्रियों को न्यूनतम असुविधा सुनिश्चित करने और साथ ही उच्चस्तर की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से अधिकांश कार्य रात्रि ब्लॉक अवधि के दौरान किए गए।

श्री विनीत ने आगे बताया कि यह क्षमता वृद्धि उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन को अधिक प्रभावी रूप से अलग करने में सक्षम बनाती है, जिससे परिचालन सुचारू रूप से होगी, कंजेशन कम होगी तथा समयपालनता में सुधार होगा। इस अतिरिक्त लाइन से मेंटेनेंस ब्लॉक और पिक ट्रैफिक अवधि के दौरान परिचालन क्षमता भी सुदृढ़ होगी, जिससे मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में सेवा की विश्वसनीयता और यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी।

इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संपर्क को अत्यंत सीमित समय-सीमा में पूरा किया जाना पश्चिम रेलवे की इंजीनियरिंग क्षमता, परियोजना प्रबंधन में अनुशासन तथा यात्री-केंद्रित विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। यह परियोजना ट्रेनों के सुचारु परिचालन में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देगी और प्रतिदिन यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेगी।

पश्चिम रेलवे निरंतर बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा विश्वसनीय, कुशल और यात्री-केंद्रित रेल सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिससे मुंबई की जीवनरेखा के रूप में उसकी भूमिका और अधिक सुदृढ़ होती है।

न उम्र की सीमा, न जाति का बंधन - बीजेपी में शुरू हुआ 'नबीन' युग

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी में आज से एक नए अध्याय की औपचारिक शुरुआत हो रही है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने जा रहे हैं। उनका चयन केवल संगठनात्मक बदलाव भर नहीं, बल्कि भाजपा की राजनीति में पीढ़ीगत परिवर्तन और वैचारिक की रणनीति का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने यह संदेश दिया है कि भाजपा में नेतृत्व का रास्ता वंश, उम्र या जातिगत समीकरणों से नहीं, बल्कि मेहनत, संगठन कौशल और वैचारिक प्रतिबद्धता से तय होता है।

सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान नितिन नबीन के पक्ष में कुल 37 सेट नामांकन दाखिल किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी सहित पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं, मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके नाम का समर्थन किया। खास बात यह रही कि उनके विरोध में एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण ने बताया कि सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं और 20 जनवरी को उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा।

भाजपा के लिए यह बदलाव केवल एक व्यक्ति का चयन नहीं, बल्कि 1980 में पार्टी की स्थापना के बाद से चली आ रही नेतृत्व परंपरा की अगली कड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे दिग्गजों ने जिस वैचारिक नींव पर पार्टी को खड़ा किया, उसे दूसरी पीढ़ी के नेताओं—नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, अमित शाह और जेपी नड्डा—ने विस्तार दिया और भाजपा

को सत्ता के शिखर तक पहुँचाया। अब नितिन नबीन के रूप में चौथी पीढ़ी के हाथों में नेतृत्व सौंपकर पार्टी ने भविष्य की राजनीति का रोडमैप साफ कर दिया है।

नितिन नबीन का राजनीतिक सफर संगठन की सीढ़ियों से होकर गुजरा है। बिहार से आने वाले नबीन पांच बार के विधायक हैं और लंबे समय तक भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उन्होंने संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और युवाओं को जोड़ने में उल्लेखनीय काम किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सहप्रभारी के रूप में उनकी रणनीतिक भूमिका को पार्टी की जीत का अहम कारण माना गया। प्रचार प्रबंधन, बूथ स्तर की योजना और कार्यकर्ताओं के समन्वय में उनकी कार्यकुशलता ने आलाकमान का भरोसा जीता, जिसके बाद दिसंबर 2025 में उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

उनकी नियुक्ति कई मायनों में ऐतिहासिक है। नितिन नबीन बिहार से भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और पार्टी के पहले कायस्थ अध्यक्ष भी। सबसे महत्वपूर्ण यह कि वे भाजपा के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी तीन बार और राजनाथ सिंह दो बार अध्यक्ष रहे, लेकिन इतनी कम उम्र में संगठन की कमान किसी को नहीं मिली थी। यह बदलाव बताता है कि भाजपा आने वाले वर्षों में युवाओं पर अधिक भरोसा करने वाली है।

नबीन ऐसे समय में पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं जब संगठन के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इनमें से बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जहाँ भाजपा अब तक सत्ता तक नहीं पहुँच पाई है। असम में तीसरी बार सरकार बनाना और पुडुचेरी में सत्ता बरकरार रखना भी आसान नहीं होगा। इन राज्यों में संगठन विस्तार, क्षेत्रीय समीकरणों की समझ और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करना नबीन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि युवा अध्यक्ष नई ऊर्जा के साथ जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे।

भाजपा के अंदर लंबे समय से यह चर्चा थी कि संगठन को नई पीढ़ी के हिसाब से ढालने की जरूरत है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार, डेटा आधारित चुनाव प्रबंधन और युवाओं की आकांक्षाओं को समझने वाला नेतृत्व आज की राजनीति की अनिवार्यता बन चुका है। नितिन नबीन की छवि ऐसे नेता की है जो परंपरागत संगठन शैली के साथ आधुनिक राजनीतिक औजारों का संतुलित इस्तेमाल जानते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले एक वर्ष में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम के लगातार दौरे कर चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि भाजपा इन राज्यों को लेकर बेहद गंभीर है। अब इन प्रयासों को संगठन के स्तर पर जमीन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी नितिन नबीन के कंधों पर होगी। उन्हें न केवल चुनावी रणनीति बनानी होगी, बल्कि राज्यों में स्थानीय नेतृत्व के बीच संतुलन भी साधना होगा, जो कई जगह गुटबाजी से जूझ रहा है।

भाजपा के भीतर यह संदेश भी गया है कि पार्टी में पद केवल वरिष्ठता से नहीं मिलता। नबीन का चयन इस धारणा को मजबूत करता है कि प्रदर्शन, अनुशासन और संगठन के प्रति निष्ठा ही असली पैमाना है। इससे युवा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा हुआ है। पार्टी का मानना है कि इससे दूसरी और तीसरी कतार के नेताओं को आगे बढ़ने का भरोसा मिलेगा।

विपक्ष भी इस बदलाव को गौर से देख रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर ऐसा चेहरा चुना है जो आक्रामक भी है और संगठन के भीतर स्वीकार्य भी। नितिन नबीन को वैचारिक रूप से स्पष्ट और संवाद में सहज माना जाता है, जो आने वाले मुकाबलों में भाजपा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

कुल मिलाकर भाजपा में 'नबीन' युग की शुरुआत केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि संगठन की नई दिशा का संकेत है। पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि अब आने वाले दशक की राजनीति के लिए खुद को नए सिरे से तैयार कर रही है। अब देखना होगा कि नितिन नबीन इस भरोसे को चुनावी जीत और संगठनात्मक मजबूती में किस हद तक बदल पाते हैं। इतना तय है कि भाजपा की यात्रा में आज से एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जिसकी गूंज आने वाले वर्षों की राष्ट्रीय राजनीति में साफ सुनाई देगी।

उद्यमियों को मिला 52,300 करोड़ रुपये का ऋण

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्तीय सहयोग देने की दिशा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, सरकारी बैंकों ने डिजिटल ऋण मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत 52,300 करोड़ रुपये से अधिक राशि के लगभग 3.96 लाख एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह सफलता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2025 में शुरू किए गए डिजिटल फुटप्रिंट आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल (सीएएम) का प्रत्यक्ष परिणाम मानी जा रही है। इस नई प्रणाली के तहत ऋण आवेदकों की डिजिटल गतिविधियों और सत्यापन योग्य डेटा के आधार पर ऋण पात्रता का आकलन किया जाता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तेज हो गई है।

▸▸ डिजिटल व्यवस्था के प्रभावी होने से MSME को बड़ी राहत

▸▸ सरकारी बैंकों ने स्वीकृत किए चार लाख से अधिक ऋण

डिजिटल डेटा से होता है ऋण मूल्यांकन

क्रेडिट असेसमेंट मॉडल उपलब्ध डिजिटल जानकारियों का उपयोग कर एमएसएमई ऋणों के लिए स्वचालित मार्ग तैयार करता है। यह व्यवस्था बैंक के मौजूदा ग्राहकों के साथ-साथ नए उधारकर्ताओं के लिए भी मॉडल आधारित ऋण सीमा का निर्धारण करती है। इसके माध्यम से सभी आवेदनों पर एक समान और वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस प्रणाली के तहत केवाईसी प्रमाणीकरण, मोबाइल और ई-मेल सत्यापन, जीएसटी डेटा विश्लेषण, अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट की जांच, आयकर रिटर्न का सत्यापन तथा क्रेडिट सूचना कंपनियों के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, धोखाधड़ी की पहचान के लिए भी डिजिटल फुटप्रिंट्स का सहारा लिया जाता है। मंत्रालय के अनुसार, इस डिजिटल प्रणाली के लागू होने से एमएसएमई उद्यमियों को ऋण आवेदन के लिए बैंक शाखाओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उद्यमी 24 घंटे, वर्ष के किसी भी दिन, कहीं से भी ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से अपलोड किया जा सकता है और ऋण स्वीकृति के समय भौतिक प्रतियां जमा करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। ऋण आवेदन प्रक्रिया पूरी होते ही आवेदक को निर्णय की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाती है, जिससे समय की बचत होती है और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और सरल बन गई है। सरकार का मानना है कि यह पहल एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

समुद्री सोने की तस्करी पर बड़ा प्रहार, पालघर में 1.85 करोड़ की अंबरग्रीस के साथ दो दबोचे गए

(जीएनएस)। पालघर जिले में पुलिस ने वन्यजीव अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1.85 करोड़ रुपये मूल्य की अंबरग्रीस, जिसे आम भाषा में 'व्हेल की उल्टी' कहा जाता है, बरामद की है। यह कार्रवाई वसई पुलिस द्वारा चलाए गए सुनियोजित अभियान का परिणाम है, जिसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक महंगे दामों पर बिकने वाले इस प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी से एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार यह केवल एक खेप नहीं, बल्कि संगठित गिरोह की कड़ी का हिस्सा हो सकता है, जिसकी जड़ें देश के कई तटीय इलाकों से लेकर विदेशों तक फैली हो सकती हैं। पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले-श्रृंगी ने बताया कि नालासोपारा पूर्व इलाके में खुफिया सूचना के आधार पर जाल बिछाया गया था। लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग समुद्र तटों से अवैध रूप से अंबरग्रीस इकट्ठा कर उसे ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं। इसी सूचना पर विशेष टीम का गठन किया गया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। अभियान के दौरान जवाहर क्षेत्र के निवासी कादिर गफार करग़शरा को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके पास से 1.858 किलोग्राम वजन का मोम जैसा पदार्थ मिला, जिसकी प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि वह अंबरग्रीस ही है। अंबरग्रीस दरअसल स्पर्म व्हेल के पाचन तंत्र में बनने वाला एक दुर्लभ पदार्थ है, जो समुद्र में बहकर किनारों तक पहुंचता है। इसकी सुगंध को स्थायी बनाने की विशेष क्षमता के कारण इसका उपयोग महंगे इत्र, कॉस्मेटिक उत्पादों और पारंपरिक औषधियों में किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत सोने से भी अधिक आंकी जाती है, जिसके कारण तस्कर इसे 'समुद्री सोना' कहकर बेचते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत इसका व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है, फिर भी ऊंचे मुनाफे के लालच में इसका अवैध कारोबार लगातार जारी है।

कादिर करग़शरा से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस मामले की कड़ियां जोड़ते हुए ठाणे निवासी किशोर महादेव तपसले को भी हिरासत में लिया।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, चुनाव आयोग को 1.25 करोड़ संदिग्ध नाम सार्वजनिक करने का आदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव आयोग को ऐतिहासिक निर्देश दिए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि जिन लगभग 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम 'तार्किक विसंगति' के आधार पर संदिग्ध श्रेणी में रखे गए हैं, उनकी पूरी सूची सार्वजनिक की जाए ताकि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न हो। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मतदाता सूची से नाम हटाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संदिग्ध बताई गई सूची केवल चुनाव आयोग के दफ्तरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे ग्राम पंचायतों, ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड दफ्तरों में प्रमुखता से चस्पा किया जाए ताकि आम लोग आसानी से यह देख सकें कि उनका नाम प्रभावित हुआ है या नहीं। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सूची प्रकाशित होने के बाद नागरिकों को कम से कम 10 दिनों का समय दिया जाए, जिसमें वे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। यदि किसी व्यक्ति के कागजात अधूरे पाए जाते हैं तो उसे नए प्रमाण देने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और दस्तावेज जमा करने पर अधिकारियों द्वारा रसीद देना अनिवार्य होगा। अदालत ने साफ कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम अंततः सूची से हटाया जाता है तो चुनाव आयोग को लिखित रूप में ठोस और तार्किक कारण बताना होगा, केवल तकनीकी आधार पर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार छीना नहीं जा सकता।

सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे। जब यह जानकारी सामने आई कि आयोग के कई निर्देश आधिकारिक परिपत्र के बजाय व्हाट्सएप संदेशों के जरिए दिए जा रहे हैं, तो मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार और संवैधानिक संस्थाएं व्हाट्सएप के भरोसे नहीं चल सकतीं। किसी भी प्रशासनिक निर्णय के लिए विधिवत सर्कुलर, स्पष्ट नियम और लिखित आदेश अनिवार्य होते हैं। अदालत की यह टिप्पणी चुनाव आयोग की डिजिटल कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है और भविष्य में प्रक्रियागत सुधार का संकेत भी देती है।

मामले की सुनवाई में 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' की परिभाषा को लेकर भी तीखी बहस हुई। आयोग की ओर से यह तर्क दिया गया कि यदि मां और बेटे की उम्र में केवल 15 वर्ष का अंतर हो तो यह असंभव स्थिति है और ऐसे नाम संदिग्ध माने गए हैं। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि भारत जैसे देश में बाल विवाह की सामाजिक वास्तविकता मौजूद है, इसलिए केवल उम्र के गणित के आधार पर किसी मतदाता को फर्जी नहीं ठहराया जा सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि बंगाल में 'गांगुली', 'चटर्जी' या 'बनर्जी' जैसे उपनामों की अंग्रेजी वर्तनी अलग-अलग लिखी जाती है, लेकिन आयोग के एल्गोरिदम इन्हें दो अलग व्यक्ति मानकर नोटिस भेज दे रहे हैं। यह तकनीकी खामी लाखों निर्दोष नागरिकों के लिए मुसीबत बन गई है।

सुनवाई के दौरान एक चौंकाने वाला उदाहरण भी सामने आया, जब अदालत को बताया गया कि एल्गोरिदम की गड़बड़ी के कारण नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जैसे प्रतिष्ठित नागरिक को भी संदिग्ध मानकर नोटिस जारी कर दिया गया। इस उदाहरण ने पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बुनियादी अधिकार है और किसी मशीन या त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर के भरोसे इसे खत्म नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी निर्देश दिया कि सुनवाई केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा, स्टाफ और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि करोड़ों लोगों को अनावश्यक भागदौड़ और मानसिक तनाव का सामना न करना पड़े। अदालत ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नामों की जांच संवेदनशील विषय है, इसलिए अधिकारियों का रवैया मानवीय होना चाहिए। किसी भी नागरिक को अपराधी की तरह व्यवहार सहन नहीं करना चाहिए।

यह मामला केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि पूरे देश की मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया के लिए नजीर बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था से अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी आचरण की अपेक्षा की जाती है। अदालत ने यह संदेश दिया कि तकनीक का उपयोग सहायक उपकरण के रूप में होना चाहिए, निर्णय का अंतिम आधार मानवीय विवेक और संवैधानिक सिद्धांत ही रहेंगे।

प्रणय–राधिका रॉय को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने आयकर नोटिस रद्द कर विभाग पर लगाया जुर्माना

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को बड़ी कानूनी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस को रद्द कर दिया। अदालत ने न केवल इन नोटिसों को अवैध करार दिया, बल्कि आयकर विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला मीडिया जगत और कॉरपोरेट क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है, क्योंकि यह कर प्रशासन की मनमानी पर सख्त संदेश देता है। मामला वर्ष 2016 में जारी किए गए उन नोटिसों से जुड़ा था, जो आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए कुछ ब्याज मुक्त ऋणों के संदर्भ में भेजे गए थे। आयकर विभाग का आरोप था कि इन ऋणों के लेन–देन में कर नियमों का उल्लंघन हुआ है और इस आधार पर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू की गई थी। प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने इन नोटिसों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई कानून के विपरीत है।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट कहा कि आयकर विभाग ने बिना ठोस कानूनी आधार के दोबारा मूल्यांकन खोलने की कोशिश की, जो स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि एक ही मूल्यांकन वर्ष के लिए बार–बार पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करना करदाता के अधिकारों का हनन है और इससे अनावश्यक उत्पीड़न की स्थिति पैदा होती है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन मामलों में साधारण लागत पर्याप्त नहीं हो सकती, फिर भी सांकेतिक रूप से आयकर विभाग को प्रणय रॉय और राधिका रॉय को एक–एक लाख रुपये का भुगतान करना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि विभाग का आचरण ऐसा रहा है कि बिना दंडात्मक कार्रवाई के इसे छोड़ा नहीं जा सकता। न्यायपीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून का उद्देश्य कर वसूली के नाम पर नागरिकों को परेशान करना नहीं है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि आयकर विभाग ने इससे पहले जुलाई 2011 में भी इसी मूल्यांकन को खोला था। उसी वर्ष के लिए दोबारा नोटिस जारी करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि पुनर्मूल्यांकन की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई नया तथ्य सामने नहीं आया था, जिसके आधार पर कार्यवाही दोबारा शुरू की जाए।

अदालत ने इस तर्क को सही माना और कहा कि आयकर विभाग ने पुराने तथ्यों को ही नए सिरे से व्याख्यायित कर नोटिस जारी किए, जो विधिसम्मत नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कर कानूनों की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती जिससे करदाता हमेशा अनिश्चितता के माहौल में रहे। कानून की स्थिरता और निष्पक्षता बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

इस फैसले को प्रणय रॉय और राधिका रॉय के लिए बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से वे विभिन्न कानूनी मामलों का सामना कर रहे थे और यह प्रकरण भी उन्हीं में से एक था। अदालत के आदेश के बाद अब इस मामले में उनके खिलाफ चल रही पूरी कार्यवाही समाप्त हो गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों के लिए नजीर बनेगा।

मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में भी इस प्रकरण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीटीवी के संस्थापकों के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में कई तरह की जांच और कानूनी कार्यवाहियां चली हैं, जिन्हें लेकर अलग–अलग मत रहे हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से यह संदेश गया है कि जांच एजेंसियों को कानून के दायरे में रहते हुए ही कदम उठाने होंगे।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, पूरा विवाद आरआरपीआर होल्डिंग को दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों की प्रकृति को लेकर था। आयकर विभाग का मानना था कि इन लेन–देन से कर देयता बनती है, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह सामान्य व्यावसायिक व्यवस्था थी और इसमें किसी प्रकार की कर चोरी नहीं हुई। अदालत ने विभाग की व्याख्या को अस्वीकार कर दिया।

फैसले के बाद कानूनी हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या आयकर विभाग इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस निर्णय से उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कर विशेषज्ञों का कहना है कि पुनर्मूल्यांकन की शक्ति का दुरुपयोग देश के कई मामलों में देखा गया है। कई बार पुराने बंद हो चुके प्रकरणों को फिर से खोल दिया जाता है, जिससे उद्योग और कारोबार जगत में अस्थिरता पैदा होती है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश ऐसे रुझानों पर अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी रेखांकित किया कि सरकारी एजेंसियों को निष्पक्षता और पारदर्शिता के उच्च मानदंडों का पालन करना चाहिए। किसी भी नागरिक के खिलाफ कार्रवाई ठोस साक्ष्यों और स्पष्ट कानूनी प्रावधानों पर आधारित होनी चाहिए, न कि अनुमान या पूर्वाग्रह पर।

प्रणय रॉय और राधिका रॉय की ओर से इस फैसले का स्वागत किया गया है। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि यह सत्य और न्याय की जीत है। उन्होंने हमेशा कानून में विश्वास जताया और अंततः अदालत से उन्हें न्याय मिला।

यह प्रकरण केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की कर व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों से भी जुड़ा है। अदालत के सख्त रुख ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रशासनिक शक्तियां असीमित नहीं हैं और उन पर संवैधानिक नियंत्रण बना रहेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्णय आने वाले समय में कर कानूनों की व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन की सीमाओं को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे करदाताओं में भरोसा मजबूत होगा कि अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो न्यायपालिका उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। फिलहाल यह फैसला प्रणय–राधिका रॉय के लिए राहत भरा अध्याय साबित हुआ है और आयकर विभाग के लिए आत्ममंथन का विषय।

सोना वायदा 1.45 लाख रुपये और चांदी वायदा 3.04 लाख रुपये के नए शिखर पर: क्रूड ऑयल वायदा 63 रुपये फिसला

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 244270.04 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 56746.91 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 187508.13 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 39812 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 4441.5 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 46765.46 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 143321 रुपये के भाव पर खूलकर, 145500 रुपये के ऑल टाइम हाई और 143320 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 142517 रुपये के पिछले बंद के सामने 2379 रुपये या 1.67 फीसदी की मजबूती के साथ 144896 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 1402 रुपये या 1.21 फीसदी की तेजी के संग 117210 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 203 रुपये या 1.4 फीसदी की तेजी के संग 14694 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 142680 रुपये के भाव पर खूलकर, 144895 रुपये के दिन के उच्च और 142680 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 2280 रुपये या 1.6 फीसदी की तेजी के संग 144552 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 143879 रुपये के भाव पर खूलकर, 145189 रुपये के दिन के उच्च और 143300 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 142913 रुपये के पिछले बंद के सामने 1802 रुपये या 1.26 फीसदी की तेजी के संग 144715 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 293100 रुपये के भाव पर खूलकर, 304200 रुपये के ऑल टाइम हाई और 293100 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 287762 रुपये के पिछले बंद के सामने 14918 रुपये या 5.18 फीसदी की बढ़त के साथ 302680 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 14547 रुपये या 5.02 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 304594 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 14579 रुपये या 5.03

फीसदी की तेजी के संग 304671 रुपये प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 4677.70 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 9 रुपये या 0.7 फीसदी की तेजी के संग 1298.5 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 1.2 रुपये या 0.38 फीसदी बढ़कर 314 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.65 रुपये या 0.52 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 318.15 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 50 पैसे या 0.26 फीसदी चढ़कर 191.9 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5299.48 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5423 रुपये के भाव पर खूलकर, 5435 रुपये के दिन के उच्च और 5351 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 63 रुपये या 1.16 फीसदी गिरकर 5386 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 60 रुपये या 1.1 फीसदी गिरकर 5388 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 283.7 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 322.3 रुपये और नीचे में 283.6 रुपये पर

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 56746.91 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 187508.13 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 46765.46 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 39812 पॉइंट के स्तर पर

पहुंचकर, 280.4 रुपये के पिछले बंद के सामने 37.3 रुपये या 13.3 फीसदी की तेजी के संग 317.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 37.2 रुपये या 13.26 फीसदी की तेजी के संग 317.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 973 रुपये पर खूलकर, 50 पैसे या 0.05 फीसदी की नरमी के साथ 975 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 21515.48 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 25249.98 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 3845.95 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 273.89 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 66.49 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 471.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 577.98 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 4704.95 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.77 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन कैंडी के वायदाओं में 0.19 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 20476 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 78121 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26473 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 383183 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 44463 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14129 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 38608 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 100614 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17062 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 41259 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 39610 पॉइंट पर खूलकर, 39939 के उच्च और 39102 के नीचले स्तर को छूकर, 1172 पॉइंट बढ़कर 39812 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 43.8 रुपये की गिरावट के साथ 226 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 11.1 रुपये की बढ़त के साथ 13.7 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 760 रुपये की बढ़त के साथ 1736.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6913 रुपये की बढ़त के साथ 15823.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 67 पैसे की नरमी के साथ 17.85 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 37 पैसे की नरमी के साथ 1.7 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 19 रुपये की बढ़त के साथ 245.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 23.3 रुपये की गिरावट के साथ 10.15 रुपये हुआ। सोना जनवरी 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 527 रुपये की गिरावट के साथ 346.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 8592.5 रुपये की गिरावट के साथ 12900 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 9.44 रुपये की गिरावट के साथ 19.1 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 33 पैसे की नरमी के साथ 0.5 रुपये हुआ।